



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042025-262686
CG-DL-E-25042025-262686

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2025/वैशाख 5, 1947

No. 222]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2025/VAISAKHA 5, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 261(अ).— केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि 381(अ), तारीख 27 जून, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (26) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"(27) भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी)।"

[फा. सं. पी.12011/2/2009-इएस सेल-डीओआर]

शंकर लाल कुमावत, निदेशक (एचक्यूआर.)

टिप्पणः - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना सा.का.नि 381 (अ) तारीख 27 जून, 2006 में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें सा.का.नि 929(अ) तारीख 29 दिसंबर 2009, सा.का.नि 763(अ), तारीख 15 सितंबर, 2010, सा.का.नि 957(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2010, सा.का.नि 735(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 2012, सा.का.नि 30(अ) , तारीख 17 जनवरी, 2014, सा.का.नि 564(अ), तारीख 6 अगस्त, 2014, सा.का.नि 970(अ), तारीख 15 दिसंबर, 2015, सा.का.नि 136(अ), तारीख 17 फरवरी, 2017, सा.का.नि 437(अ), तारीख 08 मई, 2018, सा.का.नि 674(अ), तारीख 25 जुलाई, 2018, सा.का.नि 24(अ), तारीख 11 जनवरी, 2018, सा.का.नि.152(अ) तारीख 01 मार्च, 2021 और सा.का.नि. 491(अ), तारीख 7 जुलाई, 2023 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2025

G.S.R. 261(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 66 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 381(E), dated the 27th June, 2006, namely:-

In the said notification, after serial number (26) and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:—

“(27) Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C).”.

[F. No. P.12011/2/2009-ES Cell-DOR]

SHANKAR LAL KUMAWAT, Director (Hqr.)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 381(E), dated the 27th June, 2006 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 929(E), dated the 29th December 2009, G.S.R. 763(E), dated the 15th September, 2010, G.S.R. 957(E), dated the 7th December, 2010, G.S.R. 735(E), dated the 1st October, 2012, G.S.R. 30(E), dated the 17th January, 2014, G.S.R. 564(E), dated the 6th August, 2014, G.S.R. 970(E), dated the 15th December, 2015, G.S.R. 136(E), dated the 17th February, 2017, G.S.R. 437(E), dated the 8th May, 2018, G.S.R. 674(E), dated the 25th July, 2018, G.S.R. 24(E), dated the 11th January, 2019, G.S.R. 152 (E) dated the 1st March, 2021 and G.S.R. 491(E), dated the 07th July, 2023.